NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
मार्च 2025, नई दिल्ली

अंदर के पन्नों पर:

- पीएम ने सहकारिता क्षेत्र की प्रगति पर की समीक्षा बैठक
- कोऑपरेटिव एजुकेशन की बदलेगी दिशा

सशक्त हो रहे कोऑपरेटिव बैंक

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

अनुक्रमणिका

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-09, मार्च-2025

निदेशक मंडल एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

मजबूत बनें कोऑपरेटिव बैंक 04

'स्वावलंबिनी' से महिला उद्यमिता को बढ़ावा 05

06 सशक्त हो रहे कोऑपरेटिव बैंक

16 सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण पर आएगी नई स्कीम

एनवाईसीएस और बैक टू विलेज के होमस्टे से बढ़ रहा पर्यटन एवं रोजगार 18

सतीश मराठे: सहकारिता क्षेत्र के प्रेरक व्यक्तित्व 21

त्रिशूर में एनवाईसीएस की समीक्षा बैठक 23

गोबर 'धन' से मालामाल होंगे किसान 24

जन औषधि की तर्ज पर पशु औषधि 27

पीएलआई 2.0 की ओर बढ़े कदम 28

हकीकत में तब्दील हुए सपने 30

मजबूत बनें कोऑपरेटिव बैंक

साइबर धोखाधड़ी इनके लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि इनकी साइबर सुरक्षा प्रणाली कमजोर है जिसकी वजह से ये साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना हैं। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश, कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रशिक्षण और नियमित ऑडिट जैसे बहुआयामी उपायों को अपनाने की जरूरत है। साथ ही, रिजर्व बैंक को और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी बैंकों की तमाम कमजोरियों को दूर कर उन्हें पुनर्जीवित और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका परिचालन सामान्य बैंकों की तरह हो, ग्राहकों को सभी सुविधाएं मिलें, ग्राहक आधार का विस्तार हो और उनका कारोबार बढ़े। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अंब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) बनाया गया है जो एक नियामक की तरह काम करेगा। यह अंब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा।

कमजोर नियामकीय निरीक्षण, पारदर्शिता का अभाव, राजनीतिक प्रभाव और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण जैसी चुनौतियों की वजह से कोऑपरेटिव बैंकों में अक्सर घोटाले की खबरें सामने आती रहती हैं। इससे न सिर्फ ग्राहकों की गाढ़ी कमाई डूबने का खतरा रहता है, बल्कि कोऑपरेटिव बैंकों के प्रति लोगों का भरोसा भी कम हो जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जहां नियामकीय निगरानी को सख्त बनाने के कई कदम उठाए हैं, वहीं सहकारिता मंत्रालय ने इनका कारोबार बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

इनमें सहकारी बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने, आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खोलने, ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, वाणिज्यिक बैंकों की तरह कर्ज का एकमुश्त निपटान करने, व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक करने की मंजूरी दी गई है। यही नहीं, अगले तीन साल में सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और विदेश के साथ व्यापार जैसी सेवाएं दे सकेंगे। सेवाओं का विस्तार होगा तो इन बैंकों का भी विस्तार होगा। बैंकों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) का भी लक्ष्य अपने माइक्रो फाइनेंस कारोबार की पहुंच और सेवाओं को बढ़ाना है। पिछले 20 वर्षों से हम माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत है। देशभर में फैली अपनी तीन दर्जन से अधिक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के जरिये हम अपने सदस्यों और अन्य जरूरतमंद युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। सहकार से समृद्धि के मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमारी यह कोऑपरेटिव सोसायटी युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। अपना विस्तार कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाना हमारा मकसद है।

इस समय देश में कुल 1,465 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। देश में 49 शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक हैं और 8.25 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। सरकार ने हर शहर में शहरी सहकारी बैंक बनाने और अगले पांच साल में देश के 80 जिलों में जिला सहकारी बैंक खोलने का लक्ष्य तय किया है। अभी देश में 352 जिला सहकारी बैंक हैं।

सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण से शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों के वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी जो बैंकिंग सुविधा से अछूते हैं या फिर छोटे जमाकर्ता हैं। हालांकि, साइबर धोखाधड़ी इनके लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि इनकी साइबर सुरक्षा प्रणाली कमजोर है जिसकी वजह से ये साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना हैं। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश, कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रशिक्षण और नियमित ऑडिट जैसे बहुआयामी उपायों को अपनाने की जरूरत है। साथ ही, रिजर्व बैंक को और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

'स्वावलंबिनी' से महिला उद्यमिता को बढ़ावा

युवा सहकार टीम

विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबिनी कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल छात्राओं को उनके उद्यमों को सफलतापूर्वक बनाने और बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमशील मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से इसकी शुरूआत की है।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यह कार्यक्रम युवा महिलाओं को न केवल बिजनेस वूमेन बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा बल्कि उन्हें गहनता से बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एथिक्स की भी विस्तृत जानकारी देगा।

पूर्वी क्षेत्र के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वावलंबिनी की सफल शुरूआत के बाद अब देश के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है। जिन संस्थानों में पहले इसकी शुरूआत हो चुकी है उनमें ओडिशा में आईआईटी भुवनेश्वर और उत्कल विश्वविद्यालय, शिलांग में नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), मेघालय में जोवाई और री भोई में कियांग नांगबाह सरकारी कॉलेज, मिजोरम में चम्फाई और लुंगलेई सरकारी कॉलेज, असम में गुवाहाटी के हांडिक गर्ल्स कॉलेज, दिसपुर कॉलेज और गुवाहाटी विश्वविद्यालय शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), हैदराबाद विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में भी स्वावलंबिनी का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस पहल की पहुंच बढ़ गई।

स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करना है।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, 'स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करना है। हम महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास पहल की ओर बढ़ना चाहते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है। भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हम महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में न देखें, हम महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखेंगे तो समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब एक बेटी आगे बढ़ेगी तो समाज के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे और समाज सशक्त बनेगा।'

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को समान अवसर प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, जिससे उन्हें अपने करियर में सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की दृष्टि मिली है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) ने कौशल विकास नेटवर्क (एसडीएन) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य उद्यमिता कौशल को बढ़ाना, पाठ्यक्रम विकसित करना, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और इनक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता शिक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को मजबूती मिलेगी।

सशक्त हो रहे कोऑपरेटिव बैंक

> **नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी बैंकों की तमाम कमजोरियों को दूर कर उन्हें पुनर्जीवित और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका परिचालन सामान्य बैंकों की तरह हो, ग्राहकों को सभी सुविधाएं मिलें, ग्राहक आधार का विस्तार हो और कारोबार बढ़े।**

युवा सहकार टीम

मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अभी हाल ही में सामने आए घोटाले के बाद एक बार फिर से कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज के तौर-तरीकों पर चर्चा छिड़ गई है। कमजोर नियामकीय निरीक्षण, पारदर्शिता का अभाव, राजनीतिक प्रभाव और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण जैसी चुनौतियों की वजह से घोटालेबाज कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसे कारनामों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। इससे न सिर्फ ग्राहकों की गाढ़ी कमाई डूबने का खतरा रहता है, बल्कि कोऑपरेटिव बैंकों के प्रति लोगों का भरोसा भी कम हो जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों के सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासकर, नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी बैंकों की तमाम कमजोरियों को दूर कर उन्हें पुनर्जीवित और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका परिचालन सामान्य बैंकों की तरह हो, ग्राहकों को सभी सुविधाएं मिले, ग्राहक आधार का विस्तार हो और कारोबार बढ़े।

कोऑपरेटिव बैंकों के परिचालन में पहले सबसे बड़ी बाधा नियामकीय अनिश्चितता थी क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न सहकारी कानूनों के तहत संचालित होते थे। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले इनके नियमन की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबाई) को सौंपी गई। कोऑपरेटिव बैंकों को कमर्शियल बैंकों की तरह कामकाज करने, लोन एवं अन्य सेवाएं देने की मंजूरी देने के साथ-साथ उनके ऑडिट सिस्टम में सुधार लाने की पहल की गई। इसके अलावा, 'सहकारिता में सहकार' की भावना को मजबूत करने के लिए सभी सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों में ही खाता खोलने का निर्देश दिया गया। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक शीर्ष संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) का गठन किया गया जो नियामक की तरह काम करेगा।

क्लीयरिंग भी कोऑपरेटिव बैंकों से ही

कोऑपरेटिव बैंकों को सार्वजनिक एवं निजी बैंकों की तरह प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अब कोऑपरेटिव बैंक की क्लीयरिंग कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए क्लीयरिंग हाउस बनाया जा रहा है जो अगले दो साल में अपनी सेवाएं देने लगेगा। इससे इन बैंकों को अब सार्वजनिक और निजी बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे जहां क्लीयरिंग में तेजी आएगी, वहीं भुगतान भी जल्द हो सकेगा। देश में पहली बार कोऑपरेटिव बैंकों के लिए क्लीयरिंग हाउस बनाने की कल्पना की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए भी सरकार गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और तकनीकी इनोवेशन्स को समाहित करने के लिए निगरानी की एक समिति बना रही है।

सहकारी बैंकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से की गईं महत्वपूर्ण पहलों में शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने, आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खोलने, ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, वाणिज्यिक बैंकों की तरह कर्ज का एकमुश्त निपटान करने, ग्रामीण एवं शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत होम लोन की सीमा दोगुनी से अधिक करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह, ग्रामीण सहकारी बैंक अब कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज दे सकेंगे ताकि उनके कारोबार का विविधिकरण हो सके। सभी सहकारी बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पात्र बनाया गया है।

कोऑपरेटिव बैंकों में मिलेंगी सभी सेवाएं

कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अंब्रैला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) बनाया गया है जो एक नियामक की तरह काम करेगा। इस संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये एकत्रित करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह अंब्रैला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा। एनयूसीएफडीसी के मुंबई स्थित कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन 24 जनवरी, 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंकों में अगले तीन साल में राष्ट्रीय बैंकों और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं मिलने लगेंगी जिनसे इनकी सेवाओं का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और विदेश के साथ व्यापार जैसी गतिविधियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ समाहित करने का काम 'अंब्रैला संगठन' करेगा। इसके साथ-साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और सभी कोऑपरेटिव बैंकों के अकाउंटिंग सिस्टम को एक करना इसका लक्ष्य रहेगा। सेवाओं का विस्तार होगा तो इन बैंकों का भी विस्तार होगा। बैंकों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

सहकारिता में सहकार

इस समय देश में कुल 1,465 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से लगभग आधे गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। देश में 49 शेड्यूल्ड बैंक हैं और 8.25 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। शहरी सहकारी बैंकों की 11,000 शाखाओं, 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट और 3.50 लाख करोड़ रुपये के ऋण के साथ सहकारी बैंकों की सामूहिक स्थिति मजबूत हुई है। सरकार ने हर शहर में शहरी सहकारी बैंक बनाने और अगले पांच साल में देश के 80 जिलों में जिला सहकारी बैंक खोलने का लक्ष्य तय किया है। अभी देश में 352 जिला सहकारी बैंक हैं जिनमें कुल 4.33 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि 34 राज्य सहकारी बैंकों में 2.42 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत के

कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अंब्रैला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) बनाया गया है जो एक नियामक की तरह काम करेगा। इस संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये एकत्रित करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह अंब्रैला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने में सक्षम होगा।

आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत कर रही एनवाईसीएस

मल्टी-स्टेट, मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनईसीएस) माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को सशक्त बना रही है। इसका लक्ष्य अपने सदस्यों और अन्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से उनके लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा देना है। एनवाईसीएस जन निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के मिशन के साथ 2005 से माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत है।

5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 37 शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से यह काम करती है और देशभर के सदस्यों के लिए सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करती है। जिला प्रतिनिधियों के माध्यम से 600 से अधिक जिलों में इसकी उपस्थिति है। पुणे स्थित केंद्रीय प्रशासन कार्यालय बैंकिंग और फाइनेंस में व्यापक अनुभव वाले वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा संचालित है। अपने सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाने की इसकी प्रतिबद्धता इसे व्यक्तिगत समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है जो सफलता और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। अपनी पहुंच और सेवाओं को बढ़ाने के लिए एनवाईसीएस ने इस साल के अंत तक पुणे में एक नई शाखा खोलने का लक्ष्य रखा है। लोगों की वित्तीय जरूरतों का समाधान कर उन्हें सशक्त बनाने और उनका स्थायी आर्थिक विकास करने के लिए एनवाईसीएस समर्पित है।

सरकार ने हर शहर में शहरी सहकारी बैंक बनाने और अगले पांच साल में देश के 80 जिलों में जिला सहकारी बैंक खोलने का लक्ष्य तय किया है। अभी देश में 352 जिला सहकारी बैंक हैं जिनमें कुल 4.33 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि 34 राज्य सहकारी बैंकों में 2.42 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

तहत कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेनदेन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ही करने की शुरूआत की गई है। 'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत को देश के सभी राज्यों में जमीन पर उतारने से ही सहकारिता क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा। इस देशव्यापी कदम से न सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है, बल्कि उनका कारोबार भी कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन बैंकों का कारोबार बढ़ेगा तो नौकरियों के नए अवसर भी बढ़ेंगे। देश के करीब 30 करोड़ लोग सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इन सभी लोगों का खाता या इनमें से आधे लोगों का खाता भी कोऑपरेटिव बैंक में खुलेगा तो इन बैंकों का कारोबार कितना बढ़ जाएगा। इसके अलावा, सभी तरह के पैक्स और अन्य सहकारी समितियों के भी खाते कोऑपरेटिव बैंक में खुलने से गांवों और दूरदराज के इलाके में स्थित इन बैंकों के कारोबार में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

किसानों और डेयरी क्षेत्र में लगे पशुपालकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात के दो जिलों बनासकांठा और पंचमहल और फिर पूरे गुजरात में चलाया गया था जिसे जबर्दस्त सफलता मिली। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे देशव्यापी बना दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय लेन-देन के लिए सदस्यों को माइक्रो एटीएम कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सहकारिता से जुड़े सभी लोगों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में ही खोले गए। इसके तहत सीमित अवधि में ही दोनों जिलों में चार लाख से अधिक बैंक खाते सहकारी बैंकों में खोले गए और 750 करोड़ रुपये की धनराशि जमा की गई। जबकि पूरे गुजरात में 9.40 लाख खाते खोले गए और 3,853 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई। इससे सहकारी बैंकों के साथ उनसे जुड़े लोगों को काफी लाभ हुआ। अब सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है। इस परियोजना के शुरु होने से सहकारी समितियों का वित्तीय लेन-देन आसान होगा। इस अभियान का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तरीय सहकारी बैंक के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है, जिससे सदस्यों को घर पर

ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकें। इस देशव्यापी परियोजना के शुरू होने के दो महीने के भीतर बैंक मित्रों की नियुक्ति और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लिया गया। देशभर में बैंक मित्रों की नियुक्ति से लाखों युवा लाभान्वित हुए हैं।

बैलेंस शीट में बदलाव

कोऑपरेटिव बैंकों के सशक्तिकरण और इनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और आरबीआई लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बैलेंस शीट और अकाउटिंग के प्रारूप में बदलाव किया है। यह बदलाव आधुनिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वित्तीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। इसका मकसद उभरते वित्तीय परिदृश्य और आधुनिक अकाउंटिंग मानकों के साथ तालमेल बिठाना है। इससे कोऑपरेटिव बैंक अब कमर्शियल बैंक की तरह अपनी बैलेंस शीट दुरुस्त रख पाएंगे जिससे गड़बड़ी की आशंका कम रहेगी। यह कदम कोऑपरेटिव बैंकों को न सिर्फ सशक्त बनाएगा, बल्कि इससे ग्राहकों के हितों की भी रक्षा होगी।

शहरी कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति सुधरी

कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने को लेकर उठाए कदमों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) की स्थिति में सुधार होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में जारी 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24' रिपोर्ट में कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से शहरी सहकारी बैंकों के पूंजी बफर, मुनाफा और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। हालांकि, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कर्ज और जमा में उनकी वृद्धि धीमी रही जो इस क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शार्ता है। आरबीआई के अनुसार, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (यूसीबी) ने परिचालन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल के साथ प्रशासन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने में प्रगति की है। इनमें चार-स्तरीय नियामक संरचना की शुरूआत, बोर्ड के निदेशकों और आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के साथ सीधा जुड़ाव और आईटी एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

इस रिपोर्ट में यूसीबी क्षेत्र के दीर्घकालिक समेकन प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है जो कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की वित्तीय अस्थिरता को दूर करने के लिए 2004-05 में शुरू हुई थी। 1990 के दशक में उदार लाइसेसिंग नीति अपनाने के चलते कोऑपरेटिव बैंकों की वित्तीय अस्थिरता बढ़ गई थी। उसके बाद से अब तक 156 शहरी सहकारी बैंकों का विलय हो चुका है। 2023-24 में अकेले 6 बैंकों का विलय हुआ है। इनमें से अधिकांश विलय महाराष्ट्र में हुए। उसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश में हुए।■

कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने को लेकर उठाए कदमों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) की स्थिति में सुधार होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में जारी 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24' रिपोर्ट में कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से शहरी सहकारी बैंकों के पूंजी बफर, मुनाफा और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया है।

पहले पीएमसी, अब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला

सवालों के घेरे में आरबीआई

आखिर क्या वजह है कि सहकारी बैंक बार-बार घोटाले के शिकार हो रहे हैं, रिजर्व बैंक की आंख तब खुलती है जब घोटाला हो चुका होता है। इसकी बड़ी वजहें जो समझ में आती हैं उनमें कमजोर विनियमन, निगरानी की कमी, राजनीतिक प्रभाव आदि शामिल हैं।

युवा सहकार टीम

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपये के घोटाले ने 2019 में सामने आए पीएमसी (पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव) बैंक घोटाले की याद ताजा कर दी। वह भी सहकारी क्षेत्र का बड़ा बैंक था, यह भी। वह भी दशकों पुराना बैंक था और उस पर ग्राहकों का भरोसा था, यह भी। वह भी मल्टी स्टेट शिड्यूल्ड बैंक था और उसकी दर्जनों शाखाएं थीं, यह भी। उस घोटाले में बैंक प्रबंधन के लोग शामिल थे, इसमें भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। हालांकि, अभी इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। वह भी महाराष्ट्र स्थित सहकारी बैंक था, यह भी। उस घोटाले के बारे में बैंक कर्मचारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक को वर्षों पहले संकेत दे दिए थे, लेकिन केंद्रीय बैंक ने चुप्पी साधे रखी। इस बार भी बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने 2020 में ही आरबीआई को चिट्ठी लिखकर अनियमितता की जानकारी दे दी थी मगर आरबीआई ने समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया जिसका नतीजा सामने है।

इतने सारे तथ्य एक जैसे होने के बावजूद दोनों घोटालों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि पीएमसी बैंक का घोटाला 6,500 करोड़ रुपये का था और यह 122 करोड़ रुपये का है। उस घोटाले में पीएमसी बैंक ने मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर एचडीआईएल और डीएचएफएल को करीब 6,500 रुपये का लोन देने के लिए नकली बैंक खातों का उपयोग किया था और डिपाजिट्स में हेराफेरी की थी। दोनों कंपनियां वधावन परिवार की थी। पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो चुका है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, बैंक के तत्कालीन जीएम और अकाउंट डिपार्टमेंट के प्रमुख हितेश मेहता ने बैंक की तिजोरी से धीरे-धीरे कर 122 करोड़ रुपये की नकदी निकाल ली।

आरबीआई ने बैंक का बोर्ड भंग कर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं और एक प्रशासक नियुक्त कर तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। अभी इसकी जांच चल रही है और जांच में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आखिर क्या वजह है कि सहकारी बैंक बार-बार घोटाले के शिकार हो रहे हैं, रिजर्व बैंक की आंख तब खुलती है जब घोटाला हो चुका होता है। इसकी बड़ी वजहें जो समझ में आती हैं उनमें कमजोर विनियमन, निगरानी की कमी, राजनीतिक प्रभाव आदि शामिल हैं। मगर सवाल यह भी है कि इतने सारे घोटालों के सामने आने के बावजूद केंद्रीय बैंक उन कमियों को दूर करने में अब तक क्यों नाकाम है जो इनकी वजह बनते हैं।■

गड़बड़ी करने वालों का लाइसेंस रद्द

युवा सहकार टीम

सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता और परिचालन संबंधी गड़बड़ी सामने आने पर रिजर्व बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। इसके तहत उन पर जुर्माना लगाने, लेनदेन और कर्ज देने पर पाबंदी लगाने के अलावा उनका लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। आरबीआई की हाल ही में जारी 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24' रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 24 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए। 2015-16 के बाद से इस समय तक कुल 70 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। ये मुख्य रूप से गैर-अनुसूचित श्रेणी के थे।

वित्त वर्ष 2024-25 में भी एक दर्जन से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए इन सभी बैंकों का चालू रहना जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक बताया था। इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और इनकी कमाई की संभावनाएं भी नहीं थी। यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन था। ये बैंक अपनी खराब वित्तीय स्थिति के साथ जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने में भी असमर्थ थे। बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के तहत जब किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो प्रत्येक ग्राहक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होता है।

2024-25 में इन बैंकों का लाइसेंस हुआ कैंसिल

- दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
- श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात
- द हिरीयुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक
- जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र
- सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान
- पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
- द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
- बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी
- शिम्शा सहकारी बैंक नियमिथा, मद्दूर, मंडया, कर्नाटक
- उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
- द महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम
- श्री शारदा महिला सहकारी बैंक, तुमकुर, कर्नाटक
- हरिहरेश्वर सहकारी बैंक, सतारा, महाराष्ट्र ■

वित्त वर्ष 2024-25 में भी एक दर्जन से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए इन सभी बैंकों का चालू रहना जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक बताया था। इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और इनकी कमाई की संभावनाएं भी नहीं थी।

पीएम ने सहकारिता क्षेत्र की प्रगति पर की समीक्षा बैठक

जैविक उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा देने का निर्देश

सहकारिता क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियों के विस्तार के लिए एग्रीस्टैक के उपयोग की सिफारिश

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के मसौदे पर हुई चर्चा

राष्ट्रीय सहकारिता नीति महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने पर है केंद्रित

युवा सहकार टीम

सहकारिता क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 मार्च को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से परिवर्तन लाने, 'सहकार से समृद्धि' को बढ़ावा देने, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं और सहकारिता मंत्रालय की अन्य पहलों पर चर्चा की गई। अपनी स्थापना के बाद से मंत्रालय ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों में 60 पहल की हैं। इन पहलों में राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस और कम्प्युटरीकरण परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का डिजिटलीकरण, प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सहकारी चीनी मिलों की दक्षता और स्थिरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने भारतीय सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के लिए वैश्विक सहकारिता संगठनों के साथ साझेदारी की आवश्यकता और सहकारिता संगठनों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्यात बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए सहकारिता समितियों के माध्यम से मृदा परीक्षण मॉडल विकसित करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई को रुपे केसीसी कार्ड के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया और सहकारिता संगठनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संगठनों की संपत्तियों के दस्तावेजीकरण की वकालत की। साथ ही सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा देने का सुझाव दिया। सहकारिता क्षेत्र में कृषि और संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (एग्रीस्टैक) के इस्तेमाल की सिफारिश की ताकि किसानों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। समीक्षा बैठक में स्कूलों, कॉलेजों और आईआईएम में सहकारिता पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सफल सहकारिता संगठनों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पीएम की ओर से रखा गया। युवा स्नातकों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रदर्शन के आधार पर सहकारिता संगठनों की रैंकिंग करने का भी सुझाव दिया गया ताकि प्रतिस्पर्धा और विकास को एक साथ बढ़ावा दिया जा सके।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति और पिछले साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए मंत्रालय ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना और एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करना है। इसके अलावा, सहकारिता समितियों के जमीनी स्तर पर प्रभाव को मजबूत करने और देश के समग्र विकास में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है।

भारत सरकार ने सहकारी समितियों के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को लागू किया है जिसमें पैक्स के स्तर पर 10 से अधिक मंत्रालयों की 15 से अधिक योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सहकारी व्यवसायों में विविधता आई है, अतिरिक्त आय का सृजन हुआ है, सहकारी समितियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। इन सहकारी समितियों के गठन के लिए वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। सहकारिता शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र को कुशल पेशेवर प्रदान करने के लिए देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। इसका नाम 'त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय' रखा। इस विधेयक के जल्दी ही संसद से पारित हो जाने की उम्मीद है।

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता में रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने 'सहकार से समृद्धि' के विजन को आगे बढ़ाया है। नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सहकारिता की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसलिए उन्होंने अपने शुरुआती जीवन से ही देखा है कि सहकारिता के माध्यम से कैसे समृद्धि लाई जा सकती है। उन्हें भलीभांति पता है कि अगर इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकता है। इसलिए उन्होंने 2021 में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जिसका जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा। अमित शाह भी लंबे समय तक सहकारी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और अहमदाबाद के एक शहरी सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं।

देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास, पीएम के सलाहकार अमित खरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।■

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना और एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करना है।

देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी

कोऑपरेटिव एजुकेशन की बदलेगी दिशा

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की मांग करेगा पूरा

सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से दक्षता व क्षमता निर्माण करेगा नया विश्वविद्यालय

अनुसंधान और विकास गतिविधियों में आएगी तेजी, उत्कृष्टता केंद्र भी होंगे विकसित

युवा सहकार टीम

सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने, सहकारिता क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की बढ़ती मांग को पूरा करने और इसके प्रति आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए देश में पहली बार कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। संसद के बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय-2025 विधेयक पेश करते हुए सरकार ने उम्मीद जताई कि इससे सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। गुजरात के आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा) की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए इसी परिसर में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी।

यह विश्वविद्यालय देश में सहकारी आंदोलन के जनक त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल के नाम पर बनाया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ रहे त्रिभुवनदास महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 1946 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ और आणंद सहकारी आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी उन्हें जाना जाता है। संसद में पेश विधेयक के अनुसार, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सहकारिता शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर देश में 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। सहकारिता विश्वविद्यालय देशभर में सहकारी प्रबंधन संस्थानों को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में काम करेगा। यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करेगा। इसकी स्थापना और कार्यप्रणाली से संबंधित मामलों को भी विधेयक में शामिल किया गया है।

वर्तमान समय में सहकारी शिक्षण में एकरूपता का अभाव है। डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि, बैंकिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करके यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को

सुव्यवस्थित करेगा। छात्रों, सहकारी समिति के सदस्यों और उद्योग के पेशेवरों को सशक्त बनाने के लिए भी इसमें विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह पहल अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगी, जो मौजूदा ज्ञान अंतराल को पाटेगी और वैश्विक स्तर पर भारत के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेगी। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

लोकसभा में विधेयक पेश

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक-2025 पेश किया। सरकार मानती है कि सहकारिता के मूल सिद्धांतों में शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना सहकारी क्षेत्र के सतत विकास और लचीलेपन को सुनिश्चित करने में अत्यधिक महत्व रखती है। वैश्विक सहकारिता में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। सहकारी क्षेत्र परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो क्षमता और संभावनाओं से भरा हुआ है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक सहकारी समितियों में 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से मानव संसाधन की इस बड़ी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

कुशल पेशेवरों की नई खेप

सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, सहकारी जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और विस्तार गतिविधियों को महत्व मिलेगा। विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करेगा, सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं, सरकारी योजनाओं और नियामक परिवर्तनों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित करेगा। यह वैश्विक सहकारी मॉडल, सहकारी समितियों में ब्लॉकचेन और मेंटरशिप और फंडिंग पहलों के माध्यम से सहकारी उद्यमिता को बढ़ाने की रणनीतियों पर शोध करेगा। सहकारी क्षेत्र की शिक्षा, विस्तार, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श आवश्यकताओं को पूरा करने में यह निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य ज्ञान और व्यवहार के बीच की खाई को पाटते हुए एक गतिशील संस्थान के रूप में काम करना और युवाओं को सहकारी उद्यमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

सहकारी संस्थान होंगे संबद्ध

इस विश्वविद्यालय में डेयरी, मत्स्य, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी मार्केटिंग और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को पाठ्यक्रम में खासतौर पर प्रमुखता दी जाएगी। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की अधिकता है उनमें चार से पांच कॉलेजों को सहकारी विश्वविद्लाय से संबद्ध किया जाएगा और बाकी राज्यों में एक से दो सहकारी कॉलेज इससे संबद्ध किए जाएंगे।

शोध संस्थानों के बीच बनेगा सेतु

सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करेगा, जो आईसीएआर केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सीएसआईआर संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों से संसाधनों को एकत्रित करेगा। यह पैक्स सचिवों को प्रशिक्षित करेगा और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। इससे सहकारी विकास के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। पारंपरिक एमएसपी मॉडल से आगे बढ़ाते हुए यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को बाजार-संचालित समाधान और आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहकारी मॉडल विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

अनुसंधान व विकास पर जोर

यह सहकारिता क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा और साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ऐसे केंद्र न केवल नवाचार को बढ़ावा देंगे और परिचालन दक्षता में सुधार करेंगे, बल्कि नीति निर्माताओं और सहकारी नेताओं को निर्णय लेने में भी सहायता करेंगे। सहकारी विश्वविद्यालय की शोध पहल संबद्ध संस्थानों के साथ सहयोग करके क्षेत्रीय सहकारी चुनौतियों का समाधान करेगा। सहकारी संस्थानों के शोध स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का ध्यान डेयरी, मत्स्य पालन, चीनी, सहकारी बैंकिंग, विपणन और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ाने पर होगा।

इंटरव्यू

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण पर आएगी नई स्कीम

सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने और सहकारी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करने के लिए देश में पहली बार सहकारिता विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है। हालांकि, नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) के नेतृत्व में अभी सहकारी क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण किया जा रहा है मगर आने वाले समय की मांग को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और एनसीसीटी के डायरेक्टर **कपिल मीणा** से **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने शिक्षण-प्रशिक्षण से जुड़े तमाम मुद्दों और मंत्रालय के विभिन्न कदमों पर बात की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

कोऑपरेटिव के शिक्षण-प्रशिक्षण में एनसीसीटी की क्या भूमिका है?

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण में एनसीसीटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह अपनी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा काम करता है। इसके नेटवर्क में 20 संस्थान हैं जो राज्यों की राजधानियों में हैं। इसमें दो तरह के संस्थान हैं। एक है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (आरआईसीएम), जो एक से अधिक राज्यों को देखते हैं। इस तरह से 5 आरआईसीएम हैं। दूसरा है आईसीएम (इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट) जो 14 राज्यों में है। यह मूलतः उसी राज्य में शिक्षण-प्रशिक्षण का काम देखता है जहां स्थित है। इनमें हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (एचडीसीएम) का एक फ्लैगशिप कोर्स होता है जो नौ महीने का है। इसमें विस्तार से कोऑपरेटिव सेक्टर की पूरी ट्रेनिंग दी जाती। कई राज्यों के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए जो भर्ती होती है उनके लिए यह कोर्स अनिवार्य है। जहां यह अनिवार्य है उन राज्यों में इसकी बहुत डिमांड रहती है। भर्ती के बाद राज्य सरकार उनकी फंडिंग कर उन्हें आईसीएम में नौ महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजती है। इसके बिना उनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा। यह काफी अच्छा कार्यक्रम है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान पुणे में है जिसका नाम वैमनीकॉम (वैकुंठ लाल मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट) है। यह कई तरह के कोर्स चलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कोर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए है। पिछले करीब 30 वर्षों से यहां से एमबीए करने वालों का सौ प्रतिशत कैंपस प्लेसमेंट हो रहा। उन सबका प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों, कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना मानव संसाधन है उनकी ट्रेनिंग के लिए एनसीसीटी के संसाधन पर्याप्त हैं या इसको और विस्तार देने की जरूरत है?

हमारे देश का कोऑपरेटिव सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है। 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं जिनके सदस्यों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। वर्तमान में सभी सदस्यों की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। इसके लिए संसाधन भी बहुत चाहिए। एनसीसीटी और इसके इंस्टीट्यूट सालाना करीब तीन लाख लोगों को ही ट्रेनिंग दे पाते हैं। इनमें सदस्यों के जागरूकता कार्यक्रम जो एक या दो दिन के होते हैं, से लेकर लॉन्ग टर्म कोर्स भी हैं। सदस्यों के जागरूकता कार्यक्रम अभी कम हो रहे हैं। इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग का लाभ ले सकें। इसे देखते हुए हमारे संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। इसमें अभी और इंस्टीट्यूट जोड़ने की जरूरत है। अभी 20 संस्थान हैं लेकिन इस संख्या को चार से पांच गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही हम सबकी ट्रेनिंग के लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनने से कोऑपरेटिव एजुकेशन को कितना फायदा होगा?

बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोऑपरेटिव एजुकेशन में यह बहुत बड़ा सुधार है क्योंकि देश में अभी तक कोई भी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिसका फोकस सिर्फ कोऑपरेटिव रहेगा। एग्रीकल्चर में बीएससी, एमएससी के कोर्स हैं, पीचडी भी की जाती है। मगर कोऑपरेटिव में इस तरह के कोर्स नहीं हैं। अभी एग्रीकल्चर के साथ ही कोऑपरेटिव को पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी के आने से कोऑपरेटिव पर डेडिकेटेड कोर्सेज बनना शुरू होंगे। छात्र एमफिल, पीएचडी, एमबीए आदि कर सकेंगे। यह यूनिवर्सिटी का काम होगा कि अलग-अलग कोर्स डिजाइन करें और उन्हें विभिन्न संस्थाओं में शुरू करे। एनसीसीटी और इसके 20 संस्थान भी यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर चलेगा यानी यूनिवर्सिटी हब का काम करेगी और विभिन्न संस्थान उससे एफिलिएट होंगे। यह यूनिवर्सिटी इरमा, आणंद के परिसर में बनाई जाएगी लेकिन सभी आईसीएम, आरआईसीएम, एनसीसीटी, वैमनीकॉम और राज्य सरकारों के विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन सभी के पास यह ऑप्शन रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करें। यूनिवर्सिटी भी यह प्रयास करेगी कि ये सब उससे जुड़ें।

देश में अमूल, इफको जैसे जो बड़े कोऑपरेटिव हैं या अभी जो राष्ट्रीय स्तर की तीन नई बड़ी सोसायटी बनी हैं उनके लिए आने वाले समय में व्यापक पैमाने पर सहकारिता को समर्पित मानव संसाधन की जरूरत होगी जो अभी हमारे पास नहीं हैं। इसकी कमी को यह यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें 30 अलग-अलग सेक्टर में काम हो रहा है। इनमें डेरी, फिशरीज, कृषि या हाउसिंग जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। यूनिवर्सिटी बनने से इन सबके लिए अलग-अलग कोर्स उपलब्ध होंगे जिनमें शिक्षित-प्रशिक्षित होकर युवा अपना करियर बना सकेंगे। सहकारिता की पॉलिसी बनाने में सरकार को इनपुट देने का काम भी यूनिवर्सिटी करेगी।

सहकारिता मंत्रालय एजुकेशन और ट्रेनिंग पर एक नई स्कीम लाने पर भी काम कर रहा है। देश की ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसायटी तक कैसे हमारी पहुंच बढ़े, उनकी जागरूकता और क्षमता निर्माण पर फोकस करते हुए यह स्कीम लाई जाएगी। इससे बड़ी संख्या में सहकारी क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यूनिवर्सिटी के शुरू हो जाने के बाद इस स्कीम को लाने की योजना है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में एनसीसीटी क्या-क्या कर रहा है?

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को व्यापक पैमाने पर मनाया जा रहा है। मंत्रालय के अलावा जितने भी कोऑपरेटिव हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। एनसीसीटी और इसके सभी संस्थानों ने साल भर के लिए कैलेंडर बनाया है कि इस दौरान क्या-क्या गतिविधियां की जाएंगी। हर गतिविधि में अंतरराष्ट्रीय सहकरिता वर्ष का लोगो इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर कुछ वर्कशॉप्स, सेमिनार, कुछ कार्यक्रम, वेबिनार आयोजित किए जाएंगे जिसमें विशेषज्ञ अपने विचार रख सकेंगे। इस तरह के कार्यक्रम एनसीसीटी के माध्यम से करने की योजना बनाई गई है।■

एनवाईसीएस और बैक टू विलेज के होमस्टे से बढ़ रहा पर्यटन एवं रोजगार

एनवाईसीएस और बैक टू विलेज के सहयोग से बैतूल जिले के दो गांव में बने आठ होमस्टे का हुआ उद्घाटन

मध्य प्रदेश के बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले के चार गांवों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना पर काम कर रही एनवाईसीएस एवं बैक टू विलेज

युवा सहकार टीम

गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ग्रामीण पर्यटन परियोजना का संचालन कर रहा है। वर्तमान में यह परियोजना विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से राज्य के 100 से अधिक गांवों में चल रही है। इस परियोजना के केंद्र में होमस्टे का निर्माण है। इच्छुक ग्रामीण अपने घर में अतिरिक्त कमरे एवं स्नानागार का निर्माण करवा सकते हैं जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से 40-60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। होमेस्टे के साथ-साथ कई अन्य गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। जैसे- लोकगीत, लोकनृत्य, बैलगाड़ी पर भ्रमण, कृषि पर्यटन, जंगल भ्रमण, ग्रामीण खेल-कूद, ग्रामीण पर्व-त्यौहार में भाग लेना, स्थानीय प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण इत्यादि।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी एवं बैक टू विलेज (बी2वी) सम्मिलित रूप से टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पिछले दो वर्षों से मध्य प्रदेश के बैतूल एवं छिंदवाड़ा जिले के कुल चार गांवों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। ये चारों जनजातीय गांव हैं जो पर्यटकों के अनुभव को और अधिक विशेष बनाते हैं। छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ गांव में दो होमेस्टे का उद्घाटन पिछले वर्ष किया गया था। इस गांव के पांच और होमेस्टे बन कर तैयार हैं जिनका उद्घाटन जल्दी

ही होना है। 15 फरवरी को बैतूल जिले के बाचा एवं बज्जरवाड़ा गांव के नवनिर्मित आठ होमेस्टे का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुगार्दास उईके, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री व सह जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर एवं स्थानीय विधायक (घोड़ाडोंगरी) गंगा उईके ने सम्मिलित रूप से किया। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सह संचालक एसके पांडेय, एनवाईसीएस के उपाध्यक्ष मनीष कुमार एवं बी2वी की सीईओ शिखा सिंह उपस्थित थीं।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि दुगार्दास उईके ने जनजातीय समाज की परंपराओं की विशेषता बताई और इन परंपराओं की पीछे के विज्ञान का भी वर्णन किया। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि इन महान परंपराओं और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज इन्हीं संस्कृति एवं परंपराओं को देखने देश-विदेश के लोग गांवों में आना चाहते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मोहन नागर ने इन गांवों के साथ अपने पुराने अनुभवों एवं संस्मरणों को साझा किया। उन्होंने कहा 'लगभग 15 वर्ष पहले जब मैं इस गांव में आया था तो यह गांव बहुत ही अव्यवस्थित और अस्वच्छ थे। पानी की कमी के कारण किसान केवल वर्षा आधारित खेती ही कर पाते थे। मगर गांव के युवाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण आज ये दोनों गांव आदर्श गांव बन गए हैं। बाचा तो देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसके सभी रसोई घरों में सौर-ऊर्जा चालित चूल्हा है। यह सबके सामूहिक प्रयास एवं तीव्र इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका है। अब ये गांव पर्यटन गांव भी बन चुके हैं।'

पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण

मिट्टी के घरः मिट्टी से निर्मित इन होमेस्टे की स्थापत्य कला पूर्ण रूप से ग्रामीण स्वरूप की है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। केवल स्नानागार एवं शौचालय को आधुनिक संसाधनों (टाइल्स, गीजर इत्यादि) से युक्त रखा गया है। खेतों के बीच बने इन होमेस्टे के चारों ओर हरे-भरे लहलहाते खेत पर्यटकों को अलग प्रकार की अनुभूति देते हैं।

जैविक भोजनः प्रत्येक होमेस्टे के साथ एक छोटा किचेन गार्डेन बनाया गया है ताकि पर्यटक अपनी पसंद की ताजी फल-सब्जियां स्वयं तोड़ कर ला सकें। ये गार्डेन पूरी तरह से जैविक हैं। भोजन की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि भोजन मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है जिससे भोजन अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। यहां पर्यटक मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाने का अनुभव भी ले सकते हैं।

बैलगाड़ी पर भ्रमणः आज के समय में गांवों में भी बैलगाड़ी दुर्लभ हो गई हैं। ऐसे में इन गांवों में पर्यटकों के लिए बैलगाड़ी की भी व्यवस्था है।

कृषि पर्यटनः मौसम के अनुसार पर्यटक गांव में हो रही खेती के विभिन्न क्रियाकलापों को देखने के साथ-साथ उसमें हिस्सा लेकर स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे- जुताई, बुवाई, रोपाई, कटाई इत्यादि।

गौ-पालनः इसमें पर्यटक गौशालाओं में शुल्क देकर गायों के साथ समय बिताते हैं। गायों को खिलाना, उन्हें सहलाना और दूध निकालने का अनुभव शहरों से आए पर्यटकों को रोमांचित करता है।

ग्रामीण खेलकूदः अब गांवों में भी ग्रामीण खेलों का प्रचलन तेजी से कम हो रहा है। इस परियोजना के माध्यम से ऐसे लुप्त होते ग्रामीण

बाचा देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसके सभी रसोई घरों में सौर-ऊर्जा चालित चूल्हा है। यह सबके सामूहिक प्रयास एवं तीव्र इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका है। अब ये गांव पर्यटन गांव भी बन चुके हैं।

होमस्टे में केंद्रीय मंत्री का रात्रि विश्राम

केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और मोहन नागर ने बाचा के होमस्टे में रात्रि विश्राम भी किया। उन्होंने ग्रामीण भोजन का स्वाद चखा और यहां के ग्रामीणों से चौपाल पर कैम्प फायर के साथ संवाद किया। अगले दिन सुबह उन्होंने बाचा की जैविक कृषि प्रक्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न फसलों का अवलोकन किया तथा देसी चना व मटर का लुत्फ उठाया। अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- मिट्टी के बने घर, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण व देसी भोजन, होमस्टे में ठहरने का आनंद ही अलग है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि भारत के ग्राम्य जीवन का आनन्द लेना है तो बाचा व बज्जरवाड़ा ग्राम के होमस्टे में जाकर रुकें । इससे हमारे जनजाति ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी। लौटते समय उन्होंने होमस्टे के मालिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस परियोजना के केंद्र में महिलाओं को रखा गया है। महिलाएं ही होमस्टे का संचालन करती हैं। यह परियोजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खेलों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पर्यटक कबड्डी, खो-खो, पिट्ठो, कित-कित जैसे खेलों का यहां आनंद ले सकते हैं।

पर्व-त्यौहार, मेला, विवाहः गांव के पर्व-त्यौहार, मेला, विवाह आदि शहरों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। समयानुसार पर्यटक गांव में मनाए जाने वाले पर्व-त्यौहारों एवं होने वाले विवाहों को देख सकते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमः इन गांवों में लोकगीत टोली, लोकनृत्य टोली, भजन मंडली, नाटक टोली आदि भी बनाई गई हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को प्रामाणिक ग्रामीण अनुभव देते हैं। ग्रामीण पर्यटन केवल पर्यटन मात्र नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक संरक्षण का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। गांवों के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। एक सामान्य किसान के ऊपर हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण पर्यटन ग्रामीणों के लिए एक वैकल्पिक आय का स्रोत उपलब्ध कराती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए अलग से बहुत अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। गांवों में पर्यटकों के आने से होमस्टे के साथ-साथ कई नए प्रकार के रोजगार सृजित होंगे। जैसे- लोकगीत, लोकनृत्य, नाटक, हस्तशिल्प, पर्यटक गाइड, टैक्सी सेवा इत्यादि।

इस परियोजना के केंद्र में महिलाओं को रखा गया है। महिलाएं ही होमेस्टे का संचालन करती हैं। यह परियोजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे होने वाली आमदनी से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। साथ ही, विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और उनकी सामाजिक छवि भी मजबूत हो रही है।

ग्रामीण पर्यटन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम पर्यटन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य दायित्व होमस्टे की बुकिंग करना, सारे होमेस्टे के बीच समन्वय बनाए रखना एवं इस बात की चिंता करना है कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।■

सतीश मराठेः सहकारिता क्षेत्र के प्रेरक व्यक्तित्व

युवा सहकार टीम

देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सहकारिता की जड़े मजबूत कर रही सहकारी संस्था सहकार भारती के संस्थापक सदस्य और रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठे का अमृत महोत्सव समारोह मुंबई के दादर स्थित योगी सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर सहकार भारती ने उनका अभिनंदन किया और उन्हें उनके काम के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया। सहकारिता क्षेत्र के देश के बड़े नेताओं में शामिल लक्ष्मणराव इनामदार के नेतृत्व में उन्होंने काम किया और उनसे प्रेरणा लेकर सहकार भारती को सींचते रहे जिसकी बदौलत आज यह सहकारी संस्था वट वृक्ष की तरह विशाल पेड़ बन पाई है।

लक्ष्मणराव इनामदार की शिक्षा 'संस्कार बिना सहकार नहीं' पर विश्वास करते हुए सतीश मराठे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कृति को विकसित किया और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। आज यह सहकार भारती के रूप में हमारे सामने है। इस अवसर पर सतीश मराठे ने सहकार भारती की स्थापना को याद करते हुए बताया, 'सहकार भारती की स्थापना सिर्फ पांच कार्यकर्ताओं के साथ की गई थी। देशभर में भ्रमण करते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी और यशवंतराव केलकर जैसे व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते

सहकार भारती के संस्थापक सदस्य और रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठे का अमृत महोत्सव समारोह मुंबई में आयोजित

सहकार भारती ने सतीश मराठे को उनके काम के लिए किया सम्मानित, बड़े नेताओं ने उनके काम को किया याद

भैयाजी जोशी ने मराठे को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि शुद्ध, निष्पक्ष भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता ही संगठन को महान बनाते हैं। वहीं, सुरेश प्रभु ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सतीश मराठे के साथ काम करने की यादें ताजा कीं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया और स्पष्ट किया कि अब अगली पीढ़ी के कार्यकताओं को सतीश मराठे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।

रहे। अब सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बनने का सफर तय कर चुकी है। अब हमें इससे आगे जाना है।"

इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जोशी और सहकारी क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ देशभर से सहकार भारती के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी डिजिटल माध्यम से समारोह में भाग लिया और सतीश मराठे को शुभकामनाएं दीं।

भैयाजी जोशी ने मराठे को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि शुद्ध, निष्पक्ष भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता ही संगठन को महान बनाते हैं। वहीं, सुरेश प्रभु ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सतीश मराठे के साथ काम करने की यादें ताजा कीं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया और स्पष्ट किया कि अब अगली पीढ़ी के कार्यकताओं को सतीश मराठे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। समारोह में सतीश मराठे पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

त्रिशूर में एनवाईसीएस की समीक्षा बैठक

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस), केरल की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 21 फरवरी को त्रिशूर में आयोजित की गई। इस बैठक में एनवाईसीएस के शीर्ष नेतृत्व सहित राज्य की विभिन्न शाखाओं के प्रमुख और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का प्रमुख एजेंडा पिछले दस महीनों (अप्रैल 2024-जनवरी 2025) में सभी शाखाओं के व्यापक प्रदर्शन की समीक्षा करना था। प्रदर्शन की समीक्षा के साथ बैठक में भविष्य के लिए रणनीति भी बनाई गई।

एनवाईसीएस के अध्यक्ष राजेश पांडे, संस्थापक अध्यक्ष वी. मुरलीधरन, निदेशक एडवोकेट बालू और सीईओ डॉ. रामचंद्र कुलकर्णी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 11 शाखाओं के शाखा अध्यक्ष, सचिव और प्रबंधकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस मौके पर राजेश पांडे और वी. मुरलीधरन ने प्रत्येक शाखा की प्रगति और उनके सामने आई चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए गहन मूल्यांकन किया। एनवाईसीएस की केरल स्थित शाखाओं ने बैठक में अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट पेश की और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान रचनात्मक चर्चाएं हुई जिसमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से दक्षता और आउटरीच बढ़ाने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश गए। साथ ही, प्रतिभागियों को अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और संगठन के समग्र विकास में योगदान देने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बैठक में विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। पलक्काड से देवदासन और प्रवीण ने हिस्सा लिया, जबकि कन्नडी का प्रतिनिधित्व रमेश और पंकजाक्षन ने किया। मधादास और रघुनाथ ने मुंडूर से और राधाकृष्णन एवं विश्वनाथन ने तिरुविल्वामाला का प्रतिनिधित्व किया। कुन्नमकुलम का प्रतिनिधित्व उल्लास और दामोदरन ने किया। कोडुंगल्लूर से शशिधरन और विजयगोपाल, त्रिपुनिथुरा से सोमनाथन और सतीश, अलुवा से मुरलीधरन और संतोष इस बैठक में शामिल हुए। राजगोपालन और शिबिन ने चेलक्कारा से, चलाकुडी से एडवोकेट रोश और संजयन और त्रिशूर से राजेश और अनंतकृष्ण की मौजूदगी रही।

संगठनात्मक उत्कृष्टता के प्रति सभी शाखाओं की प्रतिबद्धता के साथ बैठक का समापन हुआ। एनवाईसीएस के शीर्ष अधिकारियों ने टीमों के समर्पित प्रयासों की सराहना की और उनसे लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया। यह आयोजन सामूहिक विकास और क्षेत्रीय सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम था।

एनवाईसीएस की केरल स्थित शाखाओं ने बैठक में अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट पेश की और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान रचनात्मक चर्चाएं हुई जिसमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से दक्षता और आउटरीच बढ़ाने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश गए।

गोबर 'धन' से मालामाल होंगे किसान

एनडीडीबी ने 15 राज्यों के 26 दुग्ध संघों से बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किया एमओयू

लघु, छोटे और बड़े बायोगैस प्लांट के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता, 1000 करोड़ रुपये के आवंटन से नई वित्त पोषण योजना की शुरूआत

किसानों, गौशालाओं और डेरी फार्म से खरीदा जाएगा गोबर, स्लरी और जैविक खाद का होगा निर्माण

युवा सहकार टीम

श्वेत क्रांति-2 के माध्यम से डेरी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई-नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत अब सिर्फ दूध उत्पादन को ही बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि गाय और भैंसों के गोबर से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। इसका जिम्मा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को दिया गया है। एनडीडीबी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसका विस्तार अब देशभर में करने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में एनडीडीबी ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 'डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला' में 15 राज्यों के 26 दुग्ध संघों से देशभर में बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे डेरी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर एक है और विश्व की डेरी है। डेरी क्षेत्र कृषि जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडिशन) में 30 प्रतिशत योगदान देता है।

इस मौके पर एनडीडीबी के लघु और बड़े पैमाने पर बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं और टिकाऊ डेरी हस्तक्षेपों के वित्त पोषण के लिए एनडीडीबी सस्टेन प्लस परियोजना के तहत वित्त पोषण पहलों का भी शुभारंभ किया गया। छोटे और बड़े बायोगैस संयंत्रों और संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनडीडीबी ने 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नई वित्त पोषण योजना शुरू की है। इससे अगले 10 वर्षों में विभिन्न खाद प्रबंधन मॉडलों को बढ़ाने में सुविधा होगी जिससे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। इन पहलों से डेरी फार्मिंग में चक्रीय प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाने, कुशल खाद प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने तथा पर्यावरणीय प्रभावों के कम होने की उम्मीद है।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करते

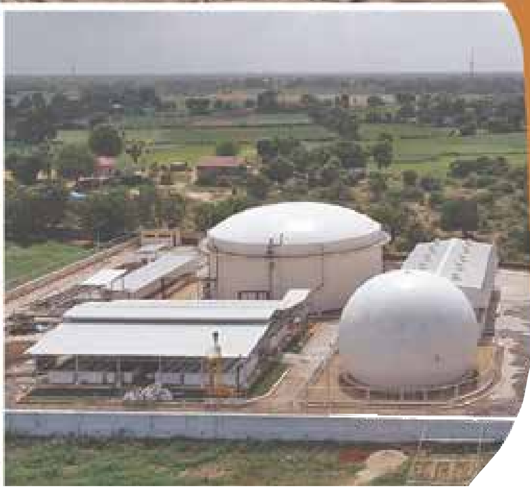

हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, 'गांवों से पलायन रोकने और भूमिहीन एवं छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेरी क्षेत्र महत्वपूर्ण विकल्प है। श्वेत क्रांति-2 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है। सस्टेनेबिलिटी, कुशलता और संसाधनों की सर्कुलरिटी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' का विजन साकार होगा। आज जब हम श्वेत क्रांति-2 की तरफ बढ़ रहे हैं तब सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी का महत्व बहुत बढ़ गया है। श्वेत क्रांति-1 से अब तक हमने जो हासिल किया है उससे सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है।' अमित शाह ने श्वेत क्रांति-2 के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य स्तरीय संघ और देश के 80 प्रतिशत जिलों में दुग्ध संघ बनाने की वकालत की।

देश में 53 करोड़ से अधिक पशुधन हैं जिनमें से लगभग 30 करोड़ गाय और भैंस हैं। इसलिए बड़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध है जिसका उपयोग जैविक खाद, जैव ईंधन आदि के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को नवाचार के साथ एकीकृत करने से न केवल हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाखों किसानों की समृद्धि भी सुनिश्चित होगी।

एनडीडीबी के नेतृत्व में डेरी क्षेत्र ने स्थिरता और चक्रीयता को बढ़ाने के लिए प्रमुख खाद प्रबंधन प्रथाओं की शुरुआत की है। इसके तीन सफल मॉडलों में जकारियापुरा मॉडल, बनास मॉडल और वाराणसी मॉडल शामिल हैं जो दूध के साथ-साथ गोबर को एक मूल्यवान वस्तु के रूप में क्षमता को उजागर करते हैं। इन मॉडलों को अब देशभर में लागू किया जाएगा जिससे पशुपालक गोबर के माध्यम से न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि ईंधन और जैविक खाद के रूप में भी उनका इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐसे काम करते हैं ये मॉडल

जकारियापुरा मॉडलः गुजरात के आणंद जिले के बोरवद तालुका के जकारियापुरा गांव के तीन चौथाई से ज्यादा घरों में पशुपालन होता है जिनमें भैंसों की संख्या ज्यादा है। यहां के किसानों का मुख्य रोजगार दूध उत्पादन ही है। ये अमूल को अपना दूध बेचते हैं। पहले ये पशुपालक गोबर को इकट्ठा कर उनका इस्तेमाल खाद के रूप में अपने खेतों में करते थे। गोबर से कमाई करने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनडीडीबी ने यहां 1.2 करोड़ रुपये की लागत से सभी पशुपालकों के घरों में 2 घनमीटर के गोबर गैस प्लांट (एक प्लांट की कीमत करीब 25 हजार रुपये) लगवाए जिससे रोजाना करीब 24 हजार लीटर स्लरी (प्लांट से निकलने वाला तरल गोबर) निकलती है। स्लरी का इस्तेमाल

गांवों से पलायन रोकने और भूमिहीन एवं छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेरी क्षेत्र महत्वपूर्ण विकल्प है। श्वेत क्रांति-2 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

रोजगार के 22 लाख नए अवसर पैदा होने की उम्मीद

गोबर से कमाई करने वाले इन मॉडलों को देशभर में लागू करने के लिए ही एनडीडीबी ने दुग्ध संघों से एमओयू किया है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जैविक खाद का बड़ा बाजार तैयार करने में भी मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक, अगर यह योजना पूरे देश में लागू हो गई तो रोजगार के 22 लाख नए अवसर पैदा होंगे। बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र के सफल प्रयोगों को 2 साल के लक्ष्य के साथ 250 जिला दुग्ध उत्पादक संघों में मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक लागू करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। साथ ही, जैविक खाद का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए जिला स्तर के दुग्ध संघों और ग्रामीण डेयरियों के उन किसानों को सहकारिता से भी जोड़ने की कवायद की जाएगी जो अभी इससे नहीं जुड़े हैं। भारत की कृषि प्रणाली छोटे किसानों पर आधारित है, लेकिन शहरों की ओर इनका पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इस समस्या का समाधान करने के साथ छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत का डेरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह हमारे देश के पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है।

डेरी क्षेत्र में चक्रीयता और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ ईंधन और जैविक खाद के उत्पादन के लिए गोबर का उपयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। देश में 53 करोड़ से अधिक पशुधन हैं जिनमें से लगभग 30 करोड़ गाय और भैंस हैं। इसलिए बड़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध है जिसका उपयोग जैविक खाद, जैव ईंधन आदि के लिए किया जा सकता है।

सीधे खेतों में भी किया जाता है और इससे जैविक खाद भी बनाई जाती है। बायोगैस प्लांट लगाने के बाद अमूल के जरिये उसकी खरीद और मूल्यवर्धित कर जैविक खाद बनाई जा रही है। इससे गांव के लोगों को अतिरिक्त आमदनी होने लगी। इसके साथ कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला। इसके अलावा, प्लांट से पशुपालकों को मुफ्त में खाना पकाने के लिए बायोगैस मिलने लगा जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च बचने लगा। इससे गांव के किसानों की आमदनी तीन गुना तक बढ़ गई। आमतौर पर जो गाय-भैंस दूध नहीं देते हैं उन्हें पालना किसानों के लिए मुश्किल होता है लेकिन इस मॉडल के तहत अब ऐसे पशु भी आमदनी का जरिया बन गए हैं। इस सफल मॉडल का विस्तार अब पूरे देश में करने की तैयारी हो गई है जिसका फायदा किसानों को मिलेगा।

बनास मॉडलः गुजरात के बनासकांठा जिले की बनास डेयरी गोबर को बायोगैस और घोल (स्लरी) में बदल रही है। इसके बाद बायोगैस को शुद्ध करके बायो सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) और बायो सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्लरी को कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए जैविक खाद में बदला जाता है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। बनास डेयरी डीसा तालुक के दामा ग्राम पंचायत के आस-पास के गांवों में रहने वाले किसानों से दूध खरीदती रही है। वेस्ट टू वेल्थ की नई पहल के तहत बनास डेयरी ने फरवरी 2020 में एक बायोगैस प्लांट स्थापित किया और 254 डेयरी किसानों से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर 1:1 के अनुपात में पानी के साथ मिलाया जाता है और 2-3 घंटे बाद डाइजेस्टर (बंद टैंक) में डाल दिया जाता है जहां यह 35 दिनों तक रहता है।

गैस को बड़े गुब्बारे के आकार के टैंकों में संग्रहित किया जाता है जबकि घोल को ठोस और तरल भागों में अलग किया जाता है। ठोस भाग का उपयोग वर्मी-कम्पोस्टिंग के लिए किया जाता है और तरल भाग को प्लांट में रिसाइकिल किया जाता है या सीधे किसानों को खेतों में उपयोग के लिए बेचा जाता है। फिर कच्ची गैस को कम्प्रेस्ड किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए बनास डेयरी ने बायो सीएनजी पंप भी खोल रखा है।

वाराणसी मॉडलः इस मॉडल के तहत डेरी के पास बड़े बायोगैस प्लांट लगाए गए। प्लांट से उत्पादित बायोगैस का उपयोग डेरी प्लांट की थर्मल और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर गोबर की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति आसपास की गौशालाओं और पशुपालकों से होती है। गोबर बेचना किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त स्रोत बनता जा रहा है।■

जन औषधि की तर्ज पर पशु औषधि

पशुपालकों को पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेंगी सस्ती जेनेरिक दवाएं

पशुओं को चार प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए मोबाइल वेटनरी वैन के जरिये किसानों को घर-घर जाकर दी जाएगी सहायता

युवा सहकार टीम

देश की जनता को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की मदद से सस्ती दवा उपलब्ध कराने के अभियान की सफलता के बाद अब सरकार पशुपालकों के लिए पशुओं की सस्ती दवा उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए जनऔषधि की तर्ज पर पशु औषधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अच्छी गुणवत्ता की जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। शुरूआत में सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधन को मंजूरी मिली। डेयरी उद्योग पर बढ़ रहे फोकस को देखते हुए यह स्कीम काफी लाभदायक साबित हो सकती है। वैसे भी भारत दूध उत्पादन में नंबर वन बनने के बाद अब दूध निर्यात बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इसके लिए श्वेत क्रांति-2 की शुरूआत की गई है। इसके तहत दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मगर इसमें एक बड़ी बाधा विभिन्न बीमारियां हैं जिसकी वजह से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है। पशुपालकों को इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो उनका इलाज कराने पर खर्च करना होता है, दूसरा, उत्पादन घटने से दूध से होने वाली उनकी कमाई पर असर पड़ता है। यह योजना किसानों व पशुपालकों की इस समस्या का निदान करेगी।

कैसे मिलेगी सहायता

पशुओं को चार प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को घर-घर जाकर सहायता दी जाएगी। इन बीमारियों में खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (सीएसएफ) शामिल हैं। इसके लिए मोबाइल वेटनरी वैन की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। खासतौर पर खुरपका-मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण केंद्रित अभियान चलाए जाएंगे। पशुओं का टीकाकरण अभियान पहले से चलाया जा रहा है जिससे पशुधन स्वास्थ्य में सुधार आया है। देश के 9 राज्य एफएमडी मुक्त क्षेत्र घोषित होने के लिए तैयार हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। पशु औषधि योजना के तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। ये दवाएं पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के जरिये पशुपालकों तक पहुंचेंगी।

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के माध्यम से पशुओं के इलाज की घर-घर डिलीवरी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम पशुपालकों के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा, जिससे पशुधन की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने दो वर्षों (2024-25 और 2025-26) के लिए 3,880 करोड़ रुपये के पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) को मंजूरी दी है। पशु औषधि इस योजना में जोड़ा गया नया घटक है।■

पीएलआई 2.0 की ओर बढ़े कदम

मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) के बजट में की बढ़ोतरी

पीएलआई-1 में उत्पादन, निर्यात और निवेश तो बढ़ा मगर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में नहीं मिली अपेक्षित सफलता

पीएलआई 2.0 में रोजगार के मौके बढ़ाने पर ज्यादा फोकस होने की उम्मीद, कई शर्तें जोड़े जाने की संभावना

युवा सहकार टीम

देश की औद्योगिक प्रगति में तेजी लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मकसद से केंद्र सरकार ने उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरूआत वित्त वर्ष 2020-21 में की थी। इस योजना की अवधि पांच साल रखी गई थी जो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होते ही समाप्त हो जाएगी। पीएलआई योजना के पहले चरण ने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देने में निश्चित रूप से मदद की है, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने में यह पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा है। खासकर, रोजगार सृजन के संदर्भ में पीएलआई योजना के नतीजे मिश्रित रहे हैं। मोबाइल फोन, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑटो, आईटी हार्डवेयर और स्पेशल स्टील जैसे क्षेत्र कुछ बेहतर स्थिति में हैं, जबकि कपड़ा, उन्नत रासायनिक सेल जैसे अन्य क्षेत्र लक्ष्य से काफी नीचे हैं।

इसे देखते हुए सरकार अब इसके दूसरे चरण की तैयारी कर रही है। इस योजना के लिए 2025-26 में दिए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र परिवर्तन लाने वाले बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में पीएलआई योजना से 14 क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 750 से अधिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश, 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ है। यह इस बात को दर्शाता है कि अवसर मिलने पर उद्यमी नए क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

2020-21 से लेकर अब तक इस योजना पर 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जहां तक रोजगार की बात है, तो इसके माध्यम से अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 9.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इस योजना पर हुए खर्च की तुलना में रोजगार

के अवसर कम पैदा हुए हैं। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा पाए हैं। ऑटो और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में इस योजना से उत्पादन और निर्यात बढ़ाने में जरूर कामयाबी मिली है लेकिन इन क्षेत्रों द्वारा उन्नत तकनीक अपनाए जाने से प्रत्यक्ष रोजगार के मौके उतने नहीं बढ़े हैं जिनकी उम्मीद की गई थी।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दशार्ते हुए सरकार ने 2025-26 में पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस बार भी सबसे अधिक आवंटन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर उद्योग के हिस्से में आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए आवंटन 5,777 करोड़ रुपये (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान) से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये और ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 346.87 करोड़ से बढ़ाकर 2,818.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इसका आवंटन 45 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,148 करोड़ हो गया है। फार्मा क्षेत्र के आवंटन में करीब 300 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इसे 2150.5 करोड़ से बढ़ाकर 2444.93 करोड़ रुपये किया गया है।

पीएलआई योजना 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें से प्रत्येक को देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देने और वैश्विक बाजारों में भारत की पैठ को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है। ये क्षेत्र घरेलू उत्पादन को मजबूत करने, निर्यात को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत की व्यापक दृष्टि में योगदान देने के सरकार के लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। प्रमुख क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करना इस योजना का मकसद है।

पीएलआई योजना के अपने पहले चरण में गति पकड़ने के साथ सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या प्रोत्साहनों को इन्क्रीमेंटल सेल्स से परे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और इन्क्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स जैसे मैट्रिक्स से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पीएलआई 2.0 में वैल्यू एडिशन को बढ़ाने, स्थानीयकरण, इन्क्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स और रणनीतिक विक्रेता आधार का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया जा सकता है। वैल्यू एडिशन का प्रतिशत उन क्षेत्रों में भी सिंगल डिजिट में ही है जहां पीएलआई योजना अपेक्षाकृत सफल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के स्थानीयकरण का एक नया मामला बनाया जा रहा है क्योंकि यह एक गतिशील घरेलू बाजार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह, पीएलआई आधारित विनिर्माण को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त मैट्रिक्स के रूप में निर्यात को पूर्व शर्त के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएलआई-1 के माध्यम से जिस तरह उत्पादन, निर्यात और निवेश बढ़ाने में सफलता मिली है, उसी तरह पीएलआई 2.0 के जरिये रोजगार बढ़ाने में अपेक्षित कामयाबी मिले।

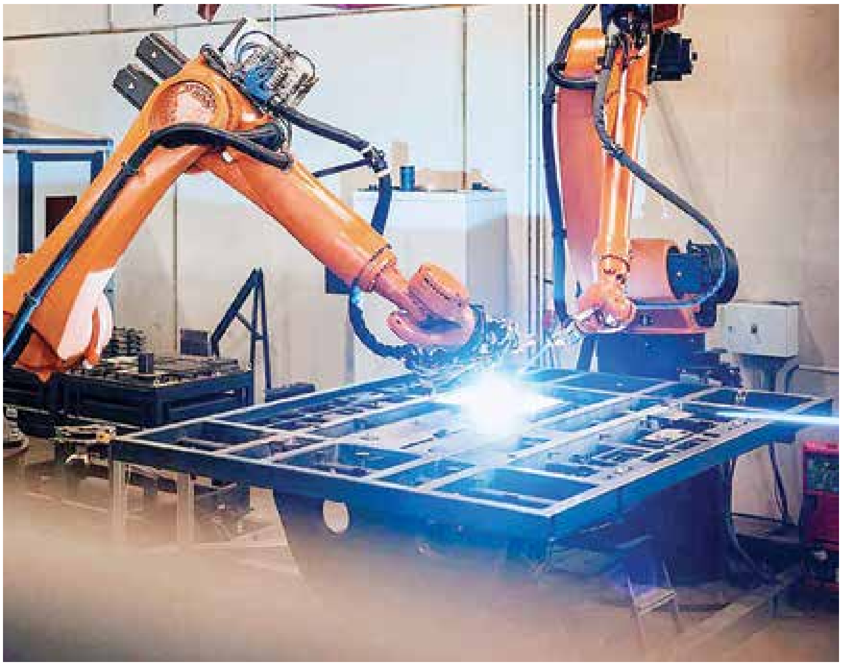

इस योजना के अंतर्गत अब तक 750 से अधिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश, 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन और 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ है। यह इस बात को दर्शाता है कि अवसर मिलने पर उद्यमी नए क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

हकीकत में तब्दील हुए सपने

वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे युवाओं को सशक्त बनाकर एनवाईसीएस उनके सपनों को कर रही साकार।

युवा सहकार टीम

महाराष्ट्र के पुणे के पास उरुलीकांचन के रहने वाले युवक अभिषेक नाहरिया का सपना उद्यमी बनने का था और वह अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते थे। फैशन के प्रति उनकी जागरूकता ने उन्हें इसी क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया। उरुलीकांचन में वह पुरुषों के कपड़ों की दुकान खोलना चाहते थे ताकि यहां के लोगों को किफायती कीमत पर स्टाइलिश कपड़े उपलब्ध करवाए जा सकें। मगर उनके पास वित्तीय संसाधन की कमी थी जिसकी वजह से उद्यमी मानसिकता के बावजूद वह अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल पा रहे थे। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) ने उनके सपने को साकार करने में मदद की जिसकी बदौलत आज वह सफल उद्यमी बनकर अपने कारोबार को विस्तार देने की ओर अग्रसर हैं।

फैशन के प्रति उनके जुनून और एक मजबूत उद्यमी मानसिकता की उनकी क्षमता को पहचानते हुए एनवाईसीएस ने उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया। एनवाईसीएस की उरुलीकंचन शाखा के माध्यम से नाहरिया ने दो लाख रुपये का लोन प्राप्त किया। इससे उन्हें अपनी दुकान स्थापित करने, गुणवत्तापूर्ण माल का स्टॉक करने और ग्राहकों के लिए आकर्षक खरीदारी का अनुभव बनाने में मदद मिली। उन्होंने उरुलीकांचन के व्यस्त इलाके में अपने सपनों की दुकान खोली।

उनका कपड़ों का स्टोर आज फल-फूल रहा है, ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहा है और उनके लिए स्थायी आय का साधन बन गया है। एक महत्वाकांक्षी उद्यमी से एक सफल व्यवसाय के मालिक बनने की उनकी यात्रा प्रेरणादायक है। अभिषेक नाहरिया की सफलता वित्तीय सशक्तिकरण के प्रभाव को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि महत्वाकांक्षा को जब सही समर्थन मिलता है, तो कैसे छोटे व्यवसाय फल-फूल सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। ऐसी प्रेरक यात्राओं का हिस्सा बनना एनवाईसीएस के लिए गर्व की बात है जो एक उद्यमी के सपनों को हकीकत में बदल देती है।

अभिषेक नाहरिया की सफलता वित्तीय सशक्तिकरण के प्रभाव को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि महत्वाकांक्षा को जब सही समर्थन मिलता है, तो कैसे छोटे व्यवसाय फल-फूल सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Business

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"